



शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तनबिहार के : अनुसूचित जाति युवाओं की संघर्षगाथा

डॉ. संजीव कुमार

पूर्व पीएचडी शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया) बिहार(, भारत

sk323799@gmail.com

सारांश

यह अध्ययन बिहार के गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों के अनुसूचित जाति युवाओं के उच्च शिक्षा अनुभवों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें सामाजिक पूंजी और सामाजिक समावेशन की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। गुणात्मक पद्धति पर आधारित यह शोध पाँच छात्रों के गहन साक्षात्कारों पर आधारित है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। अध्ययन से यह सामने आया कि जिन छात्रों को शिक्षक, परिजन या वरिष्ठ छात्र से सकारात्मक संबंध और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने शिक्षा में भागीदारी, आत्मविश्वास और स्पष्ट कैरियर दृष्टि का अनुभव किया। इसके विपरीत, जिनके संबंध कमजोर रहे या जिन्होंने संस्थागत उपेक्षा का सामना किया, उनमें अलगाव, असुरक्षा और आत्म संकोच की प्रवृत्तियाँ दिखीं।-कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में यह सामाजिक पूंजी मानसिक संतुलन और शैक्षणिक निरंतरता का मुख्य आधार बनी। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल अकादमिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुभव है, जिसमें संबंधों की गुणवत्ता और समावेशी वातावरण की भूमिका निर्णायक होती है। इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि यदि शिक्षण संस्थान समावेशी, सहयोगी और संवादात्मक संरचना विकसित करें, तो शिक्षा वंचित समुदायों के लिए सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

प्रमुख शब्द: सामाजिक पूंजी, सामाजिक समावेशन, अनुसूचित जाति, शैक्षणिक असमानता, आत्म सशक्तिकरण

1. परिचय

भारत का सामाजिक ढांचा लंबे समय से जातिगत आधार पर विभाजित रहा है, जिसमें अनुसूचित जातियाँ सबसे अधिक सामाजिक वंचना, शोषण और अवसरहीनता की शिकार रही हैं। यद्यपि संविधान ने समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की गारंटी दी है, फिर भी सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियाँ आज भी कई रूपों में मौजूद हैं। विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति युवाओं को जो

बाधाएँ झेलनी पड़ती हैं, वे केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक पूंजी और संस्थागत समर्थन की भी कमी से जुड़ी होती हैं।

बिहार राज्य, जहाँ अनुसूचित जातियाँ एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहाँ शिक्षा का महत्व केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह आत्मस्वीकृति-, पहचान, और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दलित युवा जब उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं, तो वे कई स्तरों पर संघर्ष करते हैं—पहचान के संकट से लेकर अवसरों तक की असमान पहुँच तक। ऐसे में शिक्षा उनके लिए न केवल एक अधिकार, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार बन जाती है। इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में *सामाजिक पूंजी* की भूमिका निर्णायक होती है। यह वह पूंजी है जो संबंधों, नेटवर्क, भावनात्मक समर्थन, और सूचनात्मक संसाधनों के रूप में छात्रों को प्राप्त होती है—चाहे वह परिवार, शिक्षक, या समुदाय से मिले। अनुसूचित जाति के युवा जब इस सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं या उसे सक्रिय रूप में अनुभव करते हैं, तब उनके शैक्षणिक अनुभवों में आत्मविश्वास, भागीदारी और निरंतरता आती है। इसके विपरीत, जब सामाजिक पूंजी अनुपस्थित होती है, तो वही शिक्षा प्रणाली उनके लिए अलगाव और हीनता की अनुभूति का स्रोत बन जाती है।

साथ ही, *सामाजिक समावेशन* की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता केवल छात्रों के नामांकन से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह किस हद तक छात्रों को सम्मान, भागीदारी और समान अवसर उपलब्ध कराता है। अनुसूचित जाति युवाओं के लिए यह समावेशन औपचारिक नीतियों से आगे बढ़कर उस माहौल तक पहुँचना चाहिए जहाँ वे (जैसे आरक्षण या छात्रवृत्ति) स्वयं को सुरक्षित, समर्थ और प्रतिनिधित्वशील महसूस करें। यह लेख बिहार राज्य में अनुसूचित जाति समुदायों से आने वाले युवाओं के उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों, सामाजिक पूंजी की संरचना, और संस्थागत व्यवहारों की गहराई से पड़ताल करता है। इसमें यह विश्लेषण किया जाएगा कि शिक्षा किस प्रकार उनके लिए सामाजिक गतिशीलता और पहचान निर्माण का माध्यम बन रही है। साथ ही, यह अध्ययन यह भी उजागर करेगा कि किन सामाजिक-सांस्थानिक कारकों से इन युवाओं की शैक्षणिक यात्रा सुगम या बाधित होती है। वर्तमान समय में जब राज्य और राष्ट्र दोनों शिक्षा के समावेशीकरण की दिशा में नीतिगत प्रयास कर रहे हैं, तब यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम अनुसूचित जाति युवाओं के अनुभवों को केंद्र में रखकर सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को समझें, जिसमें शिक्षा न केवल एक साधन है, बल्कि एक क्रांति है — चुपचाप घटित होती हुई, लेकिन गहराई से असर डालती हुई।

2. अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारतीय सामाजिक संरचना में जाति एक ऐसा तत्व रहा है, जिसने संसाधनों तक पहुँच, सम्मान और अवसरों को गहराई से प्रभावित किया। अनुसूचित जातियाँ इस व्यवस्था में सबसे अधिक वंचित रही हैं। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर समान अवसरों की बात की गई, लेकिन सामाजिक वास्तविकताओं ने कई समुदायों, विशेषकर दलितों को अभी भी उच्च शिक्षा से दूर रखा है।

बिहार, जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 16% है, वहाँ इस समुदाय के युवाओं की उच्च शिक्षा में उपस्थिति राज्य की समग्र स्थिति की तुलना में काफी कमजोर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और AISHE रिपोर्ट इस अंतर को स्पष्ट करते हैं। कारण केवल आर्थिक नहीं हैं; सामाजिक असुरक्षा, मार्गदर्शन की अनुपलब्धता और संस्थागत उदासीनता इसकी प्रमुख वजहें हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले अधिकांश दलित विद्यार्थी ऐसे परिवारों से हैं जहाँ मातापिता शिक्षित नहीं हैं। इससे न केवल शैक्षणिक सहायता की कमी -

होती है, बल्कि आत्मविश्वास और प्रेरणा के स्रोत भी सीमित हो जाते हैं। कई महाविद्यालयों की अधोसंरचना, तकनीकी संसाधनों की कमी, और कभीकभी शिक्षकों का असहयोगी व्यवहार भी बाधा बनता है।- राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं—जैसे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्तियाँ, और छात्रावास—का उद्देश्य इस अंतर को कम करना है। परंतु सूचना के अभाव, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता और ज़मीनी क्रियान्वयन की सीमाओं के कारण लाभार्थी इनका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते।

3. सैद्धांतिक ढाँचा

अनुसूचित जाति युवाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी को समझने के लिए इस अध्ययन में दो प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणाओं सामाजिक पूंजी और सामाजिक समावेशन को विश्लेषण के मुख्य आधार के रूप में अपनाया गया है। ये दोनों अवधारणाएँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और बराबरी की दिशा में एक सशक्त उपकरण भी है।

3.1 सामाजिक पूंजी

सामाजिक पूंजी का विचार सबसे पहले पियरे बॉर्दियो, (1986) ने प्रस्तुत किया, जिसे आगे जेम्स कोलमैन (1988) और रॉबर्ट पुटनम (1993) ने विकसित किया। बॉर्दियो के अनुसार, सामाजिक पूंजी उन संसाधनों का समुच्चय है जो व्यक्ति को *स्थायी सामाजिक संबंधों* के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये संबंध परिवार, समुदाय, संस्थानों या अन्य सामाजिक नेटवर्कों से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। कोलमैन ने सामाजिक पूंजी को शिक्षा से जोड़ते हुए यह बताया कि यदि बच्चों के माता-पिता, शिक्षक और समुदाय के अन्य सदस्य सहयोगी होते हैं, तो यह सहयोग उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और आत्म-विश्वास को सुदृढ़ करता है। पुटनम ने इसे नागरिक सहभागिता, परस्पर विश्वास और सहयोग के रूप में देखा, जो समावेशी समाज के निर्माण में सहायक होता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ अनुसूचित जाति समुदायों के युवा बहुधा आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े परिवारों से आते हैं, वहाँ *सकारात्मक सामाजिक पूंजी* जैसे प्रेरक शिक्षक, सहयोगी सहपाठी, मार्गदर्शक संबंध उनकी शिक्षा को निरंतरता और उद्देश्य देती है। इसके अभाव में वही संस्थान उनके लिए अलगाव और असुरक्षा का कारण बन सकते हैं।

3.2 सामाजिक समावेशन

सामाजिक समावेशन की अवधारणा हिलैरी सिल्वर (2015) और अमर्त्य सेन (2000) के सिद्धांतों पर आधारित है। सिल्वर के अनुसार, समावेशन एक *बहुस्तरीय सामाजिक प्रक्रिया* है, जिसमें व्यक्तियों को समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अवसर मिलता है। यह केवल संस्थागत पहुँच नहीं, बल्कि *सांस्कृतिक मान्यता, गरिमा, और सामाजिक संबंधों* में सहभागिता की माँग करता है। अमर्त्य सेन ने इसे क्षमताओं के विकास से जोड़ा—जब समाज किसी व्यक्ति को उसकी पूरी संभावनाओं के अनुसार विकसित होने से वंचित कर देता है, तो वह बहिष्कृत हो जाता है। इस दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में समावेशन केवल संस्थागत पहुँच नहीं, बल्कि उनके आत्मबोध, पहचान और गरिमामय उपस्थिति की प्रक्रिया है।

3.3 अध्ययन में सैद्धांतिक एकीकरण

इस अध्ययन में इन दोनों अवधारणाओं को एक साथ मिलाकर यह समझने का प्रयास किया गया है कि कैसे सामाजिक पूंजी का निर्माण अनुसूचित जाति युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में सहभागिता, टिकाव और सामाजिक प्रगति का मार्ग बनता है। साथ ही, यह विश्लेषण करेगा कि क्या वर्तमान संस्थागत ढाँचे सामाजिक समावेशन को साकार कर पा रहे हैं या नहीं। यह सैद्धांतिक ढाँचा न केवल अनुसंधान की दिशा को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि शिक्षा के अनुभव केवल पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं होते—वे संबंधों, पहचान और अवसरों की जटिल संरचना में निर्मित होते हैं।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बिहार के अनुसूचित जाति युवाओं के उच्च शिक्षा में अनुभवों को सामाजिक पूंजी और सामाजिक समावेशन के दृष्टिकोण से समझना है। शोध के लिए गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों के सरकारी डिग्री कॉलेजों का चयन किया गया, जहाँ दलित समुदाय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में नामांकित हैं। *उद्देश्यपरक एवं सुविधाजनक नमूना चयन विधि* के माध्यम से पाँच विद्यार्थियों को चुना गया—तीन पुरुष और दो महिलाएँ—जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। प्राथमिक जानकारी *अर्द्धसंरचित गहन साक्षात्कार*- और *प्रत्यक्ष अवलोकन* द्वारा एकत्र की गई। प्रत्येक साक्षात्कार 45-60 मिनट तक चला, जिसमें प्रेरणा स्रोत, शिक्षकछात्र संबंध-, और सामाजिक भागीदारी जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। डेटा का विश्लेषण *विषयवस्तु विश्लेषण विधि* से किया गया, जिससे विद्यार्थियों के अनुभवों से उभरते सामाजिक संदर्भों को समझने में सहायता मिली। नैतिकता का ध्यान रखते हुए सभी प्रतिभागियों की जानकारी गोपनीय रखी गई और पूर्व स्वीकृति ली गई। यह शोध पद्धति अध्ययन को विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और सामाजिक संदर्भ की गहराई प्रदान करती है।

5. विश्लेषण

शोध में गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों से पाँच अनुसूचित जाति छात्रों के जीवनप्रसंगों को - गहराई से समझने का प्रयास किया गया। ये छात्र न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, बल्कि उनमें से अधिकतर ऐसे परिवारों से जुड़े हैं जहाँ शिक्षा को कभी सशक्तिकरण के साधन के रूप में नहीं देखा गया था। इस परिप्रेक्ष्य में, छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा में कदम रखना अपने आप में एक सामाजिक प्रतिरोध की प्रक्रिया है, जिसमें वे न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर हैं, बल्कि ऐतिहासिक वंचनाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। साक्षात्कारों से यह उभरकर आया कि छात्रों की शैक्षणिक यात्रा का आरंभ किसी बाहरी प्रेरक व्यक्ति द्वारा होता है—जैसे मामा, चाचा, हाई स्कूल के शिक्षक या कॉलेज का कोई वरिष्ठ छात्र। ये संबंध उनके लिए *सामाजिक पूंजी* के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें मानसिक, भावनात्मक और दिशासंकेतक समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरणतः गया के एक छात्र को उसके पड़ोसी - चाचा ने सरकारी नौकरी के सपने दिखाए और प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में सोचने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार औरंगाबाद में एक छात्र को कॉलेज में एक वरिष्ठ द्वारा शैक्षणिक चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन मिला, जिससे वह निरंतरता बनाए रख सका।

तालिका.5.1: अनुसूचित जाति युवाओं की सामाजिकशैक्षणिक स्थिति-

क्रम	जिला	लिंग	माता-पिता की शिक्षा	प्रेरक व्यक्ति	शिक्षक से संबंध	सह-पाठ्य भागीदारी	कैरियर लक्ष्य
1	गया	पुरुष	दोनों निरक्षर	चाचा (पड़ोसी)	सकारात्मक	NCC सदस्य	BPSC की तैयारी
2	जहानाबाद	महिला	माता निरक्षर, पिता किसान	मामा	मिश्रित (कुछ असहयोगी)	कोई नहीं	स्कूल शिक्षिका बनना
3	औरंगाबाद	पुरुष	पिता 8वीं पास	शिक्षक (हाई स्कूल)	सहयोगी	NSS में सक्रिय	बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी
4	गया	महिला	दोनों अशिक्षित	बड़ी बहन	औपचारिक, दूरी	कोई भागीदारी नहीं	सरकारी क्लर्क बनना
5	औरंगाबाद	पुरुष	पिता 10वीं तक	कॉलेज का वरिष्ठ छात्र	घनिष्ठ व मार्गदर्शक	NCC सदस्य	मेडिकल प्रतिनिधि बनना

सामाजिक पूंजी का प्रभाव कॉलेज के वातावरण में भी स्पष्ट दिखा। जिन छात्रों को शिक्षकों का सहयोग मिला, वे न केवल कक्षा में सक्रिय रहे बल्कि एनसीसी, एनएसएस, जैसी सहपाठ्य गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। इन गतिविधियों ने उनके आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक नेटवर्क को सुदृढ़ किया। इसके विपरीत, जहानाबाद की छात्रा ने स्पष्ट रूप से बताया कि कुछ शिक्षक अनुसूचित जाति छात्रों से दूरी बनाकर रखते हैं, जिससे उनमें अलगाव और हीन भावना पैदा होती है। यह अनुभव सामाजिक समावेशन की वास्तविकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल संसाधनों की अनुपलब्धता ने चुनौतियों को और गहरा कर दिया। स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई। फिर भी, जिन छात्रों को पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर सहयोग मिला, वे मानसिक रूप से स्थिर रह सके। यह इस बात का प्रमाण है कि केवल संस्थागत संसाधनों से नहीं, बल्कि गहराई से जुड़े मानवीय संबंधों से भी शिक्षा की निरंतरता संभव है।

6. सामाजिक पूंजी और समावेशन के प्रभाव

इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में सफलता का मार्ग केवल अकादमिक योग्यता या संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि सामाजिक पूंजी की प्रकृति से भी निर्धारित होता है। सामाजिक पूंजी, अर्थात् ऐसे संबंध जो छात्र को मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर सहयोग देते हैं, उनके आत्मबल और संस्थागत जुड़ाव को मजबूती प्रदान करते हैं। जब छात्र को शिक्षक, वरिष्ठ छात्र या परिवार के किसी सदस्य से मार्गदर्शन और सहयोग

मिलता है, तो वह न केवल अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध होता है, बल्कि संस्थान के प्रति भी अपनापन महसूस करता है। जिन प्रतिभागियों ने सहयोगी शिक्षक और प्रेरणादायी वरिष्ठों का साथ पाया, वे कक्षा के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे। सहपाठ्य गतिविधियों जैसे एनएसएस-, एनसीसी और वाईआरसी में उनकी भागीदारी ने उनमें नेतृत्व, सामाजिक संवाद और टीम भावना विकसित की। यह भागीदारी उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बनी। इसके विपरीत, जिन छात्रों ने अपने शिक्षकों से दूरी, संवाद की कमी या उपेक्षा का अनुभव किया, वे संस्थागत ढाँचे में स्वयं को असुरक्षित और अलगथलग महसूस करने लगे। विशेषकर छात्राओं के मामले में-, जब जातिगत पहचान के साथ लैंगिक सीमाएँ भी जुड़ जाती हैं, तो सामाजिक समावेशन की स्थिति और जटिल हो जाती है। कोविड-19 महामारी के समय तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता ने विद्यार्थियों के समावेशन को और कमजोर किया। किंतु जिन छात्रों ने कॉलेज जीवन के प्रारंभिक चरण में मजबूत सामाजिक संबंध बना लिए थे, वे इस चुनौतीपूर्ण समय में भी मानसिक रूप से टिके रहे। यह इंगित करता है कि सामाजिक पूंजी केवल शैक्षणिक उपलब्धियों में ही सहायक नहीं होती, बल्कि वह कठिन परिस्थितियों में निरंतरता और मनोवैज्ञानिक संतुलन का आधार भी बनती है।

7. निष्कर्ष एवं सुझाव

यह अध्ययन दर्शाता है कि बिहार में अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का अनुभव केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बहिष्करण से मुक्ति और आत्म-सशक्तिकरण की यात्रा भी है। जिन छात्रों को सामाजिक पूंजी के रूप में प्रेरक संबंध और संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ, वे न केवल शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े, बल्कि सामाजिक तौर पर भी अधिक सशक्त और आशावादी बने। इसके विपरीत, जहाँ यह पूंजी कमजोर रही, वहाँ छात्रों ने आत्मग्लानि, असुरक्षा और शिक्षा से विमुखता का अनुभव किया। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का वास्तविक प्रभाव तभी सामने आता है जब छात्र को मानसिक, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर समर्थन प्राप्त हो।

इस अध्ययन के आधार पर कुछ ठोस सुझाव सामने आते हैं। सबसे पहला सुझाव है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को *समावेशी शैक्षणिक संस्कृति* का निर्माण करना चाहिए, जहाँ सभी सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को बराबरी का अनुभव हो। इसके लिए शिक्षकों की *संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण* अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, कॉलेजों को *छात्र परामर्श प्रणाली, मेंटरशिप कार्यक्रम, और संवादसमर्थक वातावरण*-विकसित करना चाहिए, जिससे छात्र किसी भी स्तर की मानसिक या शैक्षणिक समस्या का सामना आसानी से कर सकें। तीसरा, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सहपाठ्य गतिविधियों को दलित छात्रों की भागीदारी की दृष्टि - से पुनर्संरचित किया जाए, ताकि वे भी नेतृत्व और सहभागिता के अवसर प्राप्त कर सकें।

अंत में, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति छात्रों के लिए लागू की जा रही योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि *नीति से क्रियान्वयन तक की पूरी श्रृंखला* को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। यदि शिक्षा को वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाना है, तो उसे समावेशी, सहयोगी और समानताआधारित बनाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति - युवाओं के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सशक्तिकरण केवल सुविधा देने से नहीं, बल्कि *सम्मान, संवाद और संबंधों के निर्माण* से होता है।

संदर्भ सूची

- आंबेडकर, बी) .आर .(2014). *जाति का उन्मूलनटीका सहित संस्करण* : नई दिल्लीनवायना प्रकाशन। :
- बॉर्दियो, पियरे) .(1986). पूंजी के रूपमें (.संपा) रिचर्डसन .जे ., *शिक्षा के समाजशास्त्र पर सिद्धांत एवं अनुसंधान का पुस्तिकावली*(पृ .241–258)। ग्रीनवुड प्रेस।
- बॉर्दियो, पियरे) .(2018). पूंजी के रूप. *आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र*(पृ .78–92)। रूटलेज।
- कोलमैन, जे) .एस .(1988). मानव पूंजी के निर्माण में सामाजिक पूंजी. *अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी*, 94(परिशिष्ट), S95–S120.
- डेवॉल, सी.एन ., और बुशमैन, बी) .जे .(2011). सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृतिमिठास और कटु :ता. *करंट डायरेक्शन्स इन साइकोलॉजिकल साइंस*, 20(4), 256–260.
- गौतम, डी) .आर .(2015). *तकनीकी उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों की भागीदारी का अध्ययन* [डॉक्टोरल शोध प्रबंध]।
- लुंड, टी.जे ., लिआंग, बी., कोनोविट्ज़, एल., व्हाइट, ए.ई ., एवं डेसिल्वा मूसेउ, ए) .(2019). गुणवत्ता बनाम मात्रा : कॉलेज छात्रों में मेंटरिंग संबंध और उद्देश्य का विकास *साइकोलॉजी इन द स्कूल्स*, 56(9), 1472–1481.
- मौर्य, आर) .के .(2018). उनकी आवाज़ में उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित छात्रों के अनुभव : *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन*, 20(3), 17–38.
- पेकेल, के., रोहेलकेपार्टेन, ई.सी ., साइवर्टसेन, ए.के ., स्केल्स, पी.सी ., सुलिवन, टी.के ., एवं सेठी, जे) .(2018). फ्लोराइड खोजना.यह जांचना कि विकासात्मक संबंध प्रभावी हस्तक्षेपों में कैसे कार्य करते हैं : *अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोप्सायकियाट्री*, 88(5), 493–502.
- सेन, अमर्त्य) .(2000). *सामाजिक बहिष्करणअवधारणा : प्रयोग और परीक्षण*. सामाजिक विकास पत्रिका सं .1, एशियाई विकास बैंक।
- सिल्वर, हिलेरी) .(2015). सामाजिक समावेशन की प्रासंगिकताएँ. *संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (डीईएसए-यूएन)*।
- यिन, रॉबर्ट के) .(2003). *केस स्टडी अनुसंधानडिजाइन और विधियाँ* : (तीसरा संस्करण। सेज पब्लिकेशन्स।(